सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

◂ 1–30 जून, 2024 ◂ वर्ष : 2 ◂ अंक : 5/6

निःशुल्क प्रति

BPRD

प्रगति के नए युग की शुरुआत

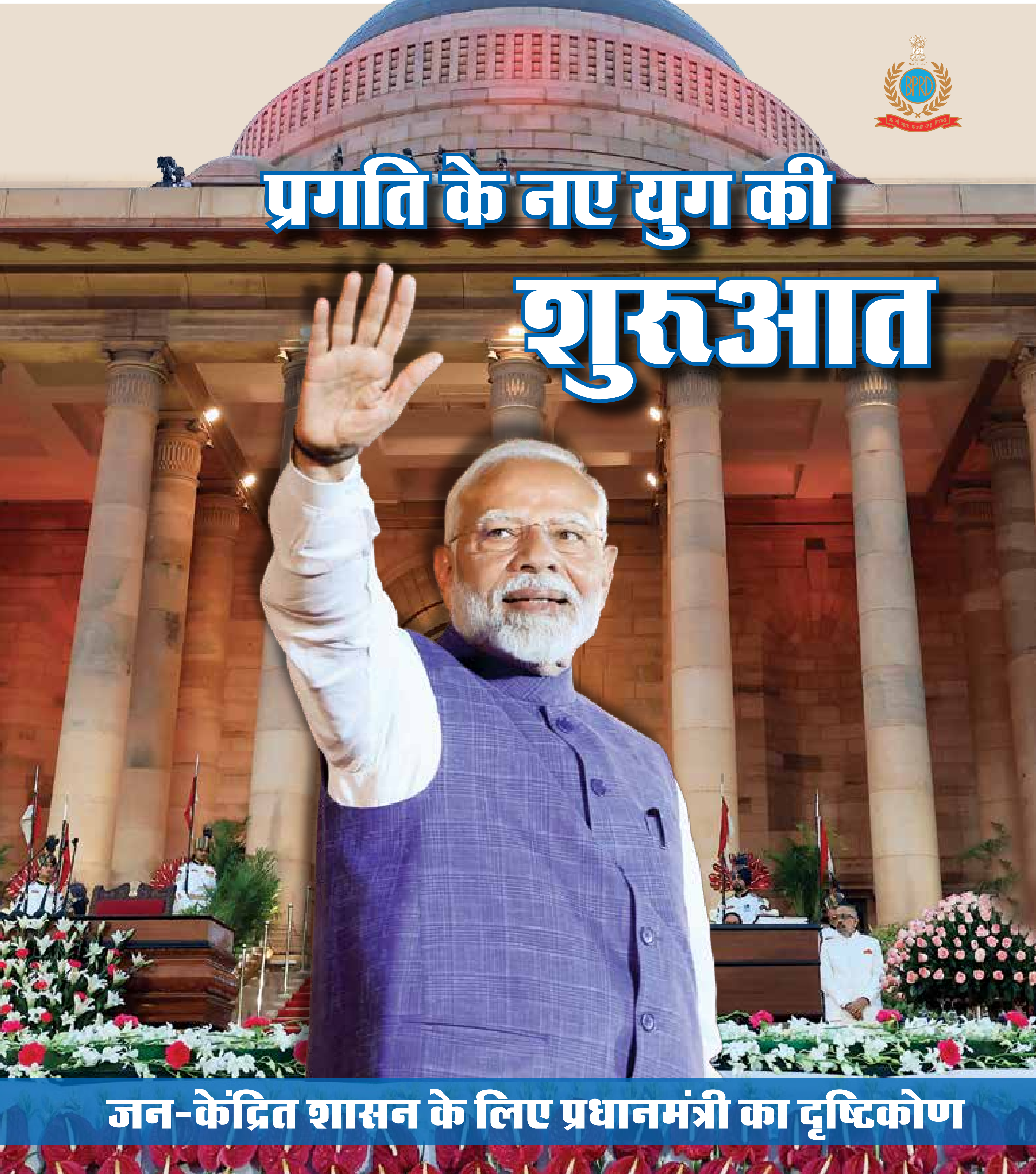

जन-केंद्रित शासन के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

हमारा लक्ष्य पीएमओ को जनता का पीएमओ बनाना है	12
कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के साथ विकसित भारत का संकल्प	14
नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है गृह मंत्रालय	15
जी 7 के मंच पर दिखा भारत का जलवा	16
नालंदा : भारत का वैश्विक ज्ञान केंद्र	23
आपदा के समय उम्मीदों पर खरी उतरती है एनडीआरएफ	25
₹36 करोड़ की लागत से बने 30 स्मार्ट स्कूलों का ई-लोकार्पण	29
केंद्रीय मंत्री परिषद	30

विशेष रिपोर्ट

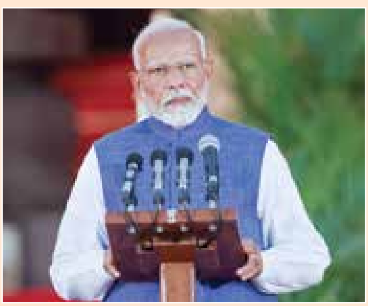

05 प्रगति के नए युग की शुरुआत

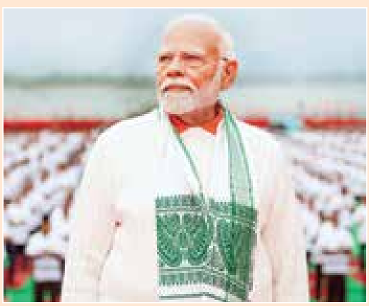

19 योग : एक एकीकृत शक्ति

27 जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई

संपादक की कलम से...

सुशासन किसी भी लोकतंत्र का आधार बनता है। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल एक ऐतिहासिक क्षण है, जो न केवल राजनीतिक निरंतरता, बल्कि परिवर्तनकारी शासन और समावेशी विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पिछले दशक में सरकार ने समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान, नवीन नीतियों और रणनीतिक पहलों के माध्यम से सर्व-समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया था। शासन में निरंतरता एक प्रगतिशील नए भारत के लिए नेतृत्व और दृष्टिकोण में लोगों के विश्वास की पुष्टि का प्रतीक है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

> **शासन में निरंतरता एक प्रगतिशील नए भारत के लिए नेतृत्व और दृष्टिकोण में लोगों के विश्वास की पुष्टि का प्रतीक है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।**

जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर ऊंचे लक्ष्य हासिल कर रहा है, पारदर्शिता, दक्षता, सुरक्षा और नागरिक-केंद्रित नीतियों को बढ़ाकर सुशासन की नींव को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में गृह मंत्रालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के पद पर हैं। उनके पहले कार्यकाल को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन जैसे ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित किया और एक अधिक एकीकृत राष्ट्र की ओर मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के साथ औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत ने आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा को दंडात्मक केंद्रित से बदलकर न्याय प्रदान करने के अनुरूप बना दिया है।

जैसे-जैसे भारत तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे केंद्र सरकार की सक्रिय विदेश नीति ने इसकी स्थिति को बढ़ाया है, निवेश आकर्षित किया है और राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है। पिछले साल भारत की मेजबानी में हुए जी 20 शिखर सम्मेलन ने बहुपक्षवाद में वैश्विक विश्वास को पुनर्जीवित किया, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के बढ़ते प्रभाव और रणनीतिक नेतृत्व को दर्शाता है।

भारत न केवल तेजी से विकास कर रहा है, बल्कि इसके विकास की गति एक बड़ी और युवा आबादी की आकांक्षाओं से भी तेजी से बढ़ रही है, जो देश के सपनों को वास्तविकता में बदलने का वादा करती है। नवोन्मेषी नीतियों और विकास रणनीतियों के साथ, देश निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

'सजग भारत' का यह अंक शासन के मील के पत्थर तथा प्रगति एवं उत्कृष्टता की दिशा में भारत की आगे की यात्रा का जश्न मनाता है। कृपया अपने विचार और प्रतिक्रिया sajag-bharat@bprd.nic.in पर साझा करें।

जय हिंद!

राजीव कुमार शर्मा

महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सरकार का मतलब सामर्थ्य, समर्पण और
संकल्पों की नई ऊर्जा है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

हम विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए कटिबद्ध रहेगी और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को एकता के सूत्र में बांधकर सशक्त भारत का निर्माण करेगी।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में हर गरीब का अपना पक्का मकान हो, इस उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित होगा।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों/सचिवों (आपदा प्रबंधन) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड और अग्निशमन सेवाओं का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 12 जून, 2024 को संपन्न हुआ।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

India is leading the global pack with a stellar GDP growth rate of 7.8%, outpacing G7 countries by a mile! Our economy is soaring high under the dynamic leadership of Hon'ble PM Shri Narendra Modi Ji. Proud to be part of a nation that's setting the pace for the world.

Shri Bandi Sanjay Kumar
Minister of State for Home Affairs

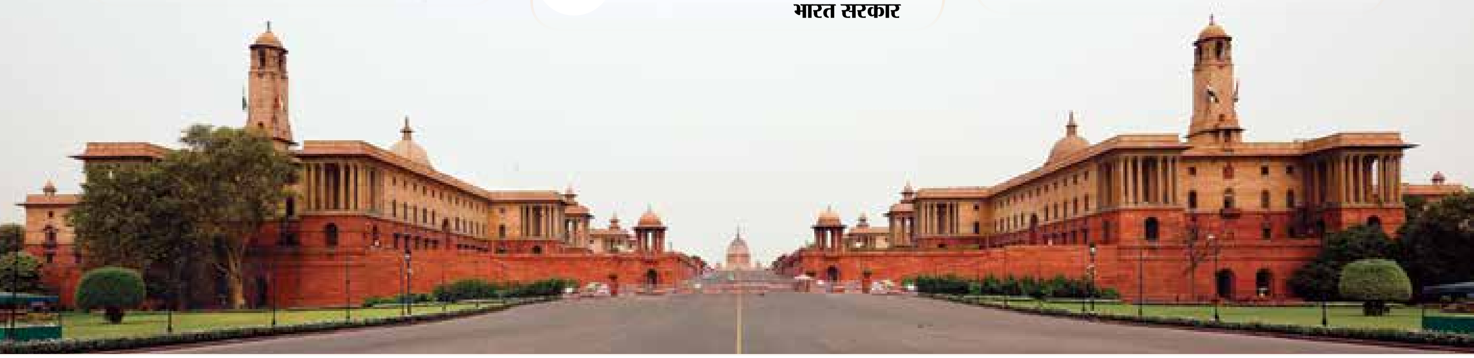

प्रगति के नए युग की शुरुआत

> मैं 140 करोड़ भारतीयों की सेवा करने और भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मंत्रिपरिषद के साथ काम करने के लिए तत्पर हूं।
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए श्री नरेन्द्र मोदी

ब्यूरो

नौ जून को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया, जिसने इस अवसर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। यह शपथ ग्रहण भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो श्री नरेन्द्र मोदी की स्थिरता और नेतृत्व की दिशा को दर्शाता है।

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में यह आयोजन न केवल राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि जन-कल्याण और विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है, जो श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2014 में पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार रही है।

हम भारत को विकसित कर विश्व अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम एक निश्चित रोडमैप के साथ इसे हासिल करने जा रहे हैं और मैंने पहले भी कहा है कि हर पल देश के लिए समर्पित है। मेरा हर पल आपके लिए समर्पित है। मैं चौबीसों घंटे उपलब्ध हूं। हमें मिलकर देश को आगे ले जाना है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के बाद।

शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्री रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति, डॉ.मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति, अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, श्रीमती शेख हसीना, मॉरीशस के प्रधानमंत्री, श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ अपनी पत्नी के साथ, नेपाल के प्रधानमंत्री, श्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री, श्री शेरिंग तोबगे शामिल हुए।

सुशासन

प्रधानमंत्री, श्री मोदी के कार्यकाल की विशेषता हाशिए पर खड़े लोगों के कल्याण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना रहा है। पिछले 10 वर्षों में, केंद्र सरकार ने भारत के हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू की हैं। केंद्र सरकार 'नए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान, भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा और वामपंथी उग्रवाद का अंत करने के लिए ठोस कदम उठाएगा।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

भारत, विकसित भारत, आकांक्षी भारत' की थीम के तहत विकास के एक नए चरण की शुरुआत कर रही है, जो विकसित भारत के सपने को वास्तविकता में बदलने का प्रयास कर रही है।

गरीबी उन्मूलन

केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, और पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। 15 जनवरी, 2024 को जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र '2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' के अनुसार इस उपलब्धि का श्रेय 2013-14 से 2022-23 तक गरीबी के विभिन्न आयामों को लक्षित करने वाली सरकार की व्यापक पहलों को दिया जाता है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई), एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति, मौद्रिक पहलुओं से परे गरीबी को पकड़ती है। केंद्र सरकार के

प्रयासों ने भारत को वर्ष 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब ला दिया है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी प्रमुख पहलों ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में काफी सुधार किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया है और 81.35 करोड़ लाभार्थियों को खाद्य सामग्री प्रदान की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार सबसे कमजोर लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

कल्याणकारी उपाय

समाज में हर वर्ग का जीवन स्तर पहले से अधिक बेहतर हो, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। बीते एक दशक में केंद्र सरकार ने भारतीयों के जीवन में बदलाव के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरु की हैं। आवास, पानी, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय समावेशन जैसी आवश्यक सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था। इसने पूरे देश में व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंको में 51 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अधिक आसान हो गई है।

2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मौलिक परिवर्तनकारी अभियान रहा है। वर्ष 2019 तक भारत को 'खुले में शौच से मुक्त' बनाने का श्री मोदी का दृष्टिकोण एक सच्चे जन आंदोलन में बदल गया और अपने लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया। इस अभियान से लगभग 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और समग्र रूप से बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाएं हुईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की थी और राय दी थी कि इससे तीन लाख लोगों की जान बचाई गई।

8 अप्रैल, 2015 को शुरु की गई पीएम मुद्रा योजना ने ₹22.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ ऋणों को मंजूरी देकर देश भर में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है। इनमें से 30 करोड़ ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं, जो लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को उजागर करता है।

असाधारण पहलों में से एक है पीएम आवास योजना। जून 2015 में श्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले लोगों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाते हुए पक्के घर उपलब्ध कराना है। जून 2024 तक, 4.21 करोड़ घरों को मंजूरी दे दी गई है और अतिरिक्त 3 करोड़ परिवारों को सहायता देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार देश भर में समाज के हाशिए पर

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेते हुए श्री अमित शाह।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का विहंगम दृश्य।

रहने वाले वर्गों के उत्थान पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दृढ़ केंद्र बिंदु को दर्शाता है।

मई 2016 में शुरु की गई पीएम उज्ज्वला योजना ने 10.27 करोड़ से अधिक घरों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान किया है। हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करते हुए, प्रति वर्ष 12 रिफिल तक प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी को मंजूरी दी।

अगस्त 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.21 करोड़ से अधिक घरों में अब नल का पानी पहुंच रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य छत पर सौर पैनल के माध्यम से एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय वाली यह पहल, भारत के स्थाई ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन का समर्थन करती है।

प्रधानमंत्री ने अपने प्रशासन की आधारशिला के रूप में पंचायत से संसद

> **मोदी 3.0 में देश की सुरक्षा नीतियां नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी। भारत आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा।**
>
> **श्री अमित शाह**
>
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

तक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डाला, जिसका उदाहरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 (संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण) द्वारा दिया गया है।

आर्थिक स्थिरता एवं विकास

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, भारत वैश्विक मानकों में तेजी से आगे बढ़ा है। विभिन्न वैश्विक चुनौतियों

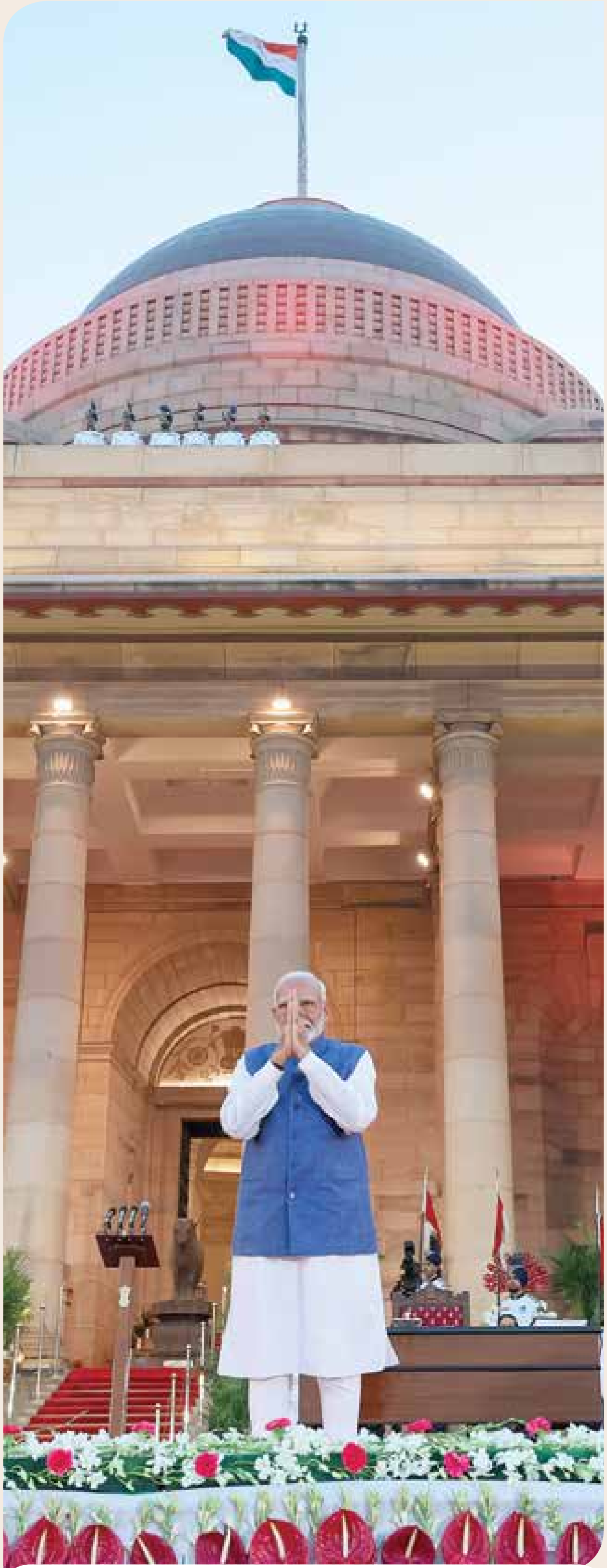

श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लोगों का अभिवादन करते हुए।

के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% की वृद्धि हुई है, जो चार में से तीन तिमाहियों में 8% के आंकड़े को पार कर गई है। यह वृद्धि स्थिर उपभोग मांग और निवेश में लगातार सुधार से प्रेरित थी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक विकास में भारत का योगदान 200 आधार अंक बढ़ जाएगा। विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और एशियाई विकास बैंक सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.1% से 6.7% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। ये अनुमान भारत के मजबूत आर्थिक प्रक्षेप पथ और देश के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय बदलाव

पिछले एक दशक में नवीन सोच और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण देश के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पहल के लिए पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने परियोजना की समय-सीमा को तेज कर दिया है, उन प्रक्रियाओं को कम कर दिया है, जिनमें कभी वर्षों लग जाते थे। इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास की यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने वाली है।

भारतीय रेलवे नए स्टेशनों, ट्रेनों और प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिकीकरण कर रहा है। दिसंबर 2023 तक 35 स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई, सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें (70 सेवाएं) शुरु की गई थीं। रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन के साथ-साथ पूर्वोत्तर में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्राथमिकता दी गई है। विद्युतीकरण एवं नये मार्गों का निर्माण हो रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। विमानन क्षेत्र में, हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 से लगभग दोगुनी होकर अब 149 हो गई है। केंद्र सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी भी दे दी है, जिनमें से 12 पहले से ही कार्यशील हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों में प्रगति भी उतनी ही प्रभावशाली रही है, नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,287 किमी से 60% बढ़कर 2023 में 1,46,145 किमी हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति में काफी वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 में 12.1 किमी/दिन से 143% बढ़कर 28.3 किमी/दिन हो गई है।

इसी तरह भारत तेजी से एक नए विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और सेवाओं से आगे बढ़कर खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों तक फैल रहा है। यह बदलाव भारतीय किसानों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), स्टार्टअप और कौशल विकास में प्रगति भारत को विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनने की ओर प्रेरित कर रही है।

बढ़ता वैश्विक प्रभाव

वर्ष 2014 के बाद से भारत की वैश्विक धारणा में एक महत्वपूर्ण

श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के समाधिस्थल 'सदैव अटल' पर पुष्पांजलि अर्पित की।

बदलाव देखा गया है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की नई छवि को 'विश्वबंधु' के रूप में प्रस्तुत किया है। इस नई छवि का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सक्रियता और प्रभावी नीतियों के माध्यम से हुआ है। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत किया है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाई है और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और योगदान को स्पष्ट किया है।

सरकार की विदेश नीति पहल ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और भूमिका को उजागर किया है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्राएं कीं, वे वर्ष 2017 में इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री हैं। उनके नेतृत्व में, भारत जी 20 और ब्रिक्स और क्वाड शिखर सम्मेलन में सक्रिय भागीदार रहा है, जहां वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर देश के विचारों को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन की व्यापक सराहना हुई। पिछले साल जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इसके बढ़ते वैश्विक प्रभाव का उदाहरण है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के तहत, केंद्र सरकार ने परिवर्तनकारी बदलावों का वादा किया है, जो भारत की वृद्धि और समृद्धि को और बढ़ाएंगे। सरकार ने एक स्पष्ट रोडमैप और मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, देश को विकास के एक नए युग में ले जाने की योजना बनाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, केंद्र सरकार पिछले दशक में रखी गई नींव को नए जोश और ऊर्जा के साथ तैयार करेगी। अगले पांच वर्षों के लिए सरकार ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अथक प्रयास करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाओं और पहलों को लागू करने में सरकार पूरी तरह से समर्पित है।

श्री अमित शाह ने इस अवसर के महत्व को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य व्यक्त किया।

श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक मजबूत ताकत के रूप में उभरेगा। यह उनके नेतृत्व में सुरक्षा और शासन के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। श्री शाह का यह बयान भारत की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है तथा सुरक्षा और आंतरिक शांति के क्षेत्र में केंद्र की आगामी नीतियों और रणनीतियों की ओर इशारा करता है। ▪

हमारा लक्ष्य पीएमओ को जनता का

ब्यूरो

10 जून का दिन बेहद खास रहा। इस दिन प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने देश के शासन में नई ऊर्जा और प्रेरणा के उत्प्रेरक के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'शुरू से ही हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा का प्रतीक बनाना और इसे लोगों का प्रधानमंत्री कार्यालय बनाना रहा है।' उन्होंने केंद्र सरकार की शक्ति, समर्पण और संकल्प के लोकाचार को रेखांकित किया। साथ ही अत्यंत समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की तत्परता पर अपना विश्वास जताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि हजारों समर्पित लोगों द्वारा मिलकर काम करने से चलती है। इसमें नागरिक अपनी सामूहिक क्षमताओं की भव्यता के गवाह बनते हैं। उन्होंने अपने समूह दल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्र-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। इसमें शामिल था एक साथ मिलकर, विकसित भारत वर्ष 2047 के एकमात्र इरादे के साथ 'राष्ट्र प्रथम' के लक्ष्य को प्राप्त करना।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सफलता प्राप्त करने की कुंजी के रूप में दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और स्थिरता के सिद्धांतों को रेखांकित किया, विचार की स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और कार्य करने के साहस के महत्व पर जोर दिया। 'इन तीन तत्वों के साथ, विफलता अकल्पनीय होगी', उन्होंने अपने समूह दल को वैश्विक मानकों को पार करने और पिछले दशक की उपलब्धियों को पार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा।

प्रधानमंत्री कार्यालय कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों को मान्यता देते हुए, प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए श्रेय दिया। उन्होंने कहा, 'हालिया चुनाव हमारे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को प्रमाणित करते हैं'। उन्होंने अपने समूह दल से नवाचार करने और अपने प्रयासों के पैमाने को ऊंचा उठाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन उनके तीसरे कार्यकाल के लिए माहौल तैयार करता है, जो शासन, विकास और वैश्विक मंच पर एक जीवंत और समृद्ध भारत की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की विशेषता है।■

अन्नदाता सबसे पहले

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और उनमें लगभग ₹20,000 करोड़ वितरित किए जाएंगे। इस फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालने के बाद हस्ताक्षर की गई पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित है। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं।'

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के साथ अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।

पीएमओ बनाना है: श्री नरेन्द्र मोदी

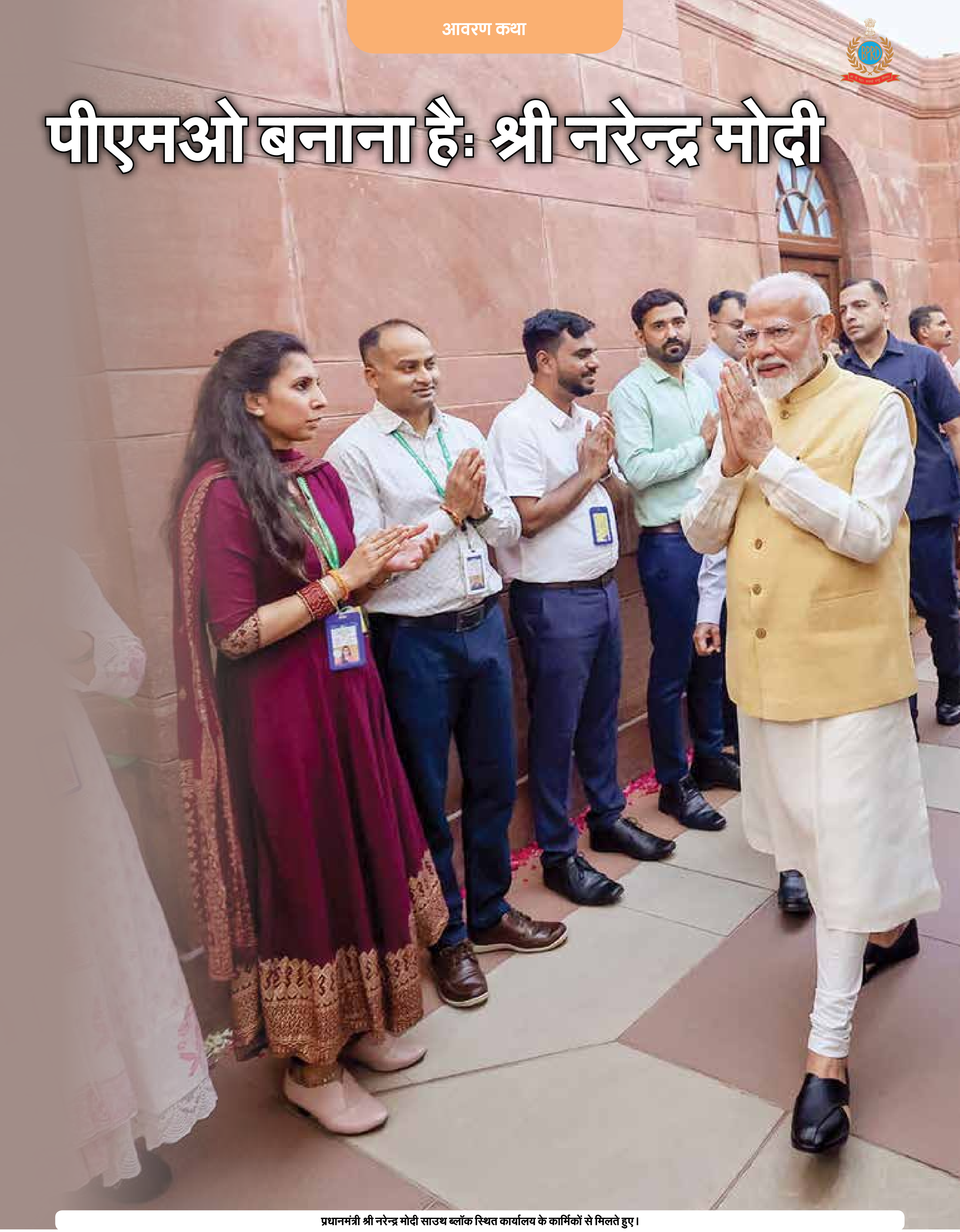

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय के कार्मिकों से मिलते हुए।

कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के साथ विकसित भारत का संकल्प

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में श्री नरेन्द्र मोदी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। बीते दस वर्षों में देश में उनके नेतृत्व में कई क्षेत्रों में प्रगति हुई। नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हुआ और भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह केवल श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दूसरी सोच के साथ विकसित भारत के संकल्प के कारण हो रहा है।

श्री नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल का कार्यकाल व्यापक सुधारों और नीतिगत पहलों से भरा रहा है। महिलाओं के जीवन स्तर पर सुधार लाने के लिए 'उज्ज्वला योजना' की शुरुआत की। भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' का मंत्र दिया। हर नागरिक स्वस्थ रहे, इसके लिए 'आयुष्मान भारत' को केंद्र सरकार ने लागू किया। जय जवान जय किसान के साथ ही जय विज्ञान को जोड़ा। लगातार 10 वर्षों तक जब प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के वीर जवानों के साथ दीवाली का त्योहार मनाया, तो जन-जन तक जय हिंद की गूंज गई।

स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जैसी योजनाओं ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को रखा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जीएसटी को लागू करके देश में नई कर व्यवस्था को मजबूत किया। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए 'जन धन योजना' की शुरूआत की। बढ़ते इंटरनेट के उपयोग से UPI का चलन भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2018 में 2071 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन अब 9500 करोड़ के पार हो चुका है। अन्नदाता मौसम की मार से परेशान न हो, इसलिए 'किसान सम्मान निधि योजना' से उन्हें समृद्ध किया। भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (GIAN) की शुरुआत हुई।

श्री नरेन्द्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिनसे देश की आंतरिक और बाह्य स्थिति मजबूत हुई है। इन निर्णयों ने न केवल भारत की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा स्थिति को सुधारने में मदद की, बल्कि देश को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समय-समय पर कई प्रकार की चुनौतियां आईं, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने हर समस्या का निराकरण किया। प्राकृतिक आपदा देश में हो या विदेश में, अपने नागरिकों तक त्वरित राहत पहुंचाई। कोरोना जैसी महामारी में देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। महामारी के दौर में एक भी व्यक्ति देश में भूखा नहीं रहे, इसके लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था कराई। 'वैक्सीन मैत्री' के तहत नब्बे से अधिक देशों को भी भारत में बना कोरोना वैक्सीन दिया। यह 'वसुधैव कुटुम्बकम' की हमारी नीति रही है।

श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की और समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन का नेतृत्व किया। अगस्त 2019 में, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित किया गया। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के संपूर्ण एकीकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। उरी (2016) और पुलवामा (2019) में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, जिससे देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूती मिली।

नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है गृह मंत्रालय

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने जैसे अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने जाने वाले, श्री अमित शाह ने 11 जून को लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्र और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। उन्होंने पुलिस और विभिन्न खुफिया एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल आतंकवादी गतिविधियों, वामपंथी उग्रवाद, नशीली दवाओं के खतरे और साइबर सुरक्षा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए जाना जाता था। उनके नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति के लिए एक मजबूत रणनीति विकसित की है। इसी तरह पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के नए रास्ते खोले हैं।

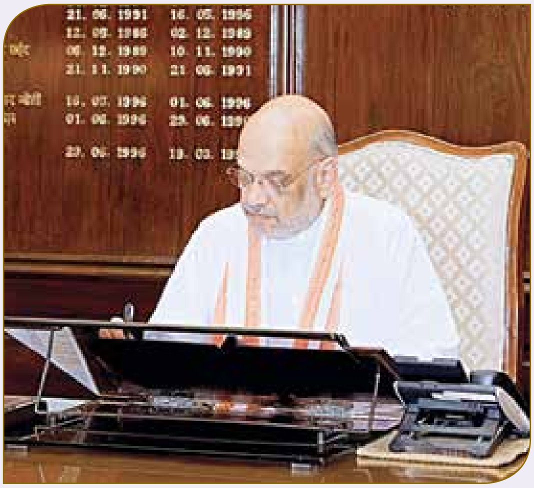

भारत की आंतरिक सुरक्षा और सहकारी आंदोलनों में अपने महत्वपूर्ण योगदान को जारी रखते हुए श्री अमित शाह को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उनके कुशल नेतृत्व में, गृह मंत्रालय का लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के सुरक्षित और समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षा पहलों को बढ़ाना है।

नशीली दवाओं के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति के तहत कार्य करते हुए, श्री शाह के पहले कार्यकाल में देश भर में नशीली दवाओं की बरामदगी और नशीली दवाओं के तस्करों की गिरफ्तारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। उनके नेतृत्व में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को काफी मजबूती मिली है। जब प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, तो श्री शाह को इसका प्रभार दिया गया। सहकारी क्षेत्र में उनका अनुभव व्यापक एवं विस्तृत है। वह इस मंत्रालय के माध्यम से सहकारी आंदोलन को वर्तमान समय की चुनौतियों के लिए तैयार करने, अस्थिरता को दूर करने, एक पारदर्शी प्रणाली बनाने और सहकारी क्षेत्र में छोटे से छोटे किसान का विश्वास बहाल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक मजबूत सहकारी आंदोलन भारत का विकास इंजन बन सकता है और देश की जीडीपी में अमूल्य योगदान दे सकता है।

दशकों से धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से, श्री शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया, जो प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। सीएए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को आशा की एक नई किरण देता है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आ गए हैं। जैसे-जैसे भारत सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, श्री शाह का योगदान भविष्य में महत्वपूर्ण रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उभरती चुनौतियों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा को लगातार सुदृढ़ करने के लिए मजबूत तैयारियों और रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया है।■

जी 7 के मंच पर दिखा भारत

इटली के अपुलिया में 50वें जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के दौरान सामूहिक तस्वीर में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष।

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इटली में जी 7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में श्री नरेन्द्र मोदी की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा रही है। यह यात्रा भारत के बढ़ते वैश्विक कद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इटली, जापान, यूक्रेन, यूके और फ्रांस के नेताओं के साथ रणनीतिक बैठकों के माध्यम से प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित किया। साथ ही वैश्विक कूटनीति के भविष्य को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की अपने लगातार तीसरे कार्यकाल की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जी 7 आउटरीच शिखर सम्मेलन रही। इटली के अपुलिया में आयोजित जी 7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भागीदारी, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित करती है। इटली की प्रधानमंत्री, सुश्री जियोर्जिया मेलोनी द्वारा आमंत्रित प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की 13-14 जून की यात्रा भारत और इटली के बीच गहरे संबंधों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का एक प्रमाण रही है।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना

13 जून को अपने प्रस्थान वक्तव्य में, प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में इटली को अपनी पहली विदेशी यात्रा बनने पर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने वर्ष 2021 में रोम में जी 20 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की अपनी यात्रा को याद किया और पिछले साल प्रधानमंत्री, सुश्री मेलोनी की दो भारत यात्राओं के प्रभाव पर प्रकाश डाला। इन यात्राओं ने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इससे भूमध्यसागरीय क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए मंच तैयार हुआ है।

का जलवा

> मुझे खुशी है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली यात्रा इटली की है। मेरी सुखद अनुभूति में शामिल है वर्ष 2021 में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए इटली यात्रा। पिछले साल प्रधानमंत्री, सुश्री मेलोनी की भारत की दो यात्राएं हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक थीं।
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

जी 7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऊर्जा दक्षता, आउटपुट और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित थीं। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन के परिणामों को जी 7 शिखर सम्मेलन के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर दिया। यह तालमेल वैश्विक चुनौतियों से निपटने और भविष्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

सभी के लिए एआई : प्रधानमंत्री की समावेशी प्रगति के लिए सोच

इटली में जी7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने समूह की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऊर्जा, ग्लोबल साउथ और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए आउटरीच सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भारत की सफलता को साझा करते हुए प्रौद्योगिकी के प्रति मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया। भारत के एआई मिशन पर प्रकाश डालते हुए, जो 'एआई फॉर ऑल' पर आधारित है, प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तकनीक का उद्देश्य प्रगति और सभी की भलाई को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत एआई के लिए वैश्विक साझेदारी का संस्थापक सदस्य है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, उन्होंने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हुए भारत के ऊर्जा संक्रमण मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने वैश्विक समुदाय को भारत के मिशन लाइफ और स्थाई भविष्य के लिए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण, विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए सम्मान की बात थी कि अफ्रीकी संघ को उसकी अध्यक्षता में जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

उच्च स्तरीय बैठकें और रणनीतिक साझेदारी

14 जून को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री, सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने भारत-इटली रणनीतिक

साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। खास यह रहा कि दोनों, भारत-इटली देशों के बीच बढ़ते व्यापार और आर्थिक सहयोग से खुश थे। खासतौर से स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों में। हाल ही में औद्योगिक संपत्ति अधिकारों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का नवाचार को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वागत किया गया। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु था। दोनों नेताओं ने रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' के तहत समन्वय को ध्यान में रखते हुए, दोनों नेताओं ने ऊर्जा परिवर्तन में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया, जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा।

भारत और इटली के लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव है, जो इटली में लंबे समय से चली आ रही इंडोलॉजिकल अध्ययन परंपरा से प्रेरित है, जो मिलान विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन पर पहली भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कुर्सी की स्थापना के साथ और मजबूत होगा। दोनों नेताओं ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का भी आह्वान किया जो सक्षम, कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों, छात्रों और शोधकर्ताओं की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाएगा।

वैश्विक सहयोग का विस्तार

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री, श्री फुमियो किशिदा के बीच द्विपक्षीय बैठक शिखर सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण बिंदु रहा। उन्होंने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के 10वें वर्ष का जश्न मनाते हुए इसके महत्व की पुष्टि की। चर्चा में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना और वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक भारत में जापान के 5 ट्रिलियन येन के लक्षित निवेश शामिल थे। यह भारत के आधारभूत संरचना और विनिर्माण क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार हैं।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति, श्री वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने बातचीत और कूटनीति के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, श्री ऋषि सुनक के साथ बैठक में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और रोडमैप-2030 की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता की स्थिति की भी समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उम्मीद जताई।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति, श्री इमैनुएल मैक्रॉन के साथ बातचीत 'होराइजन 2047' रोडमैप पर केंद्रित रही।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष श्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की।

वे रणनीतिक रक्षा सहयोग में गति लाने, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा में सहयोग का विस्तार करने और आगामी एआई शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की इटली में जी7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भागीदारी भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। इटली, जापान, यूक्रेन, यूके और फ्रांस के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकों ने मजबूत रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों को सहयोगात्मक रूप से संबोधित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। जैसे-जैसे भारत विश्व मंच पर आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व और अधिक परस्पर जुड़े और सहयोगी वैश्विक समुदाय के लिए दृष्टिकोण समृद्ध भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

योगः एक एकीकृत शक्ति

ब्यूरो

विश्व में 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। श्रीनगर में डल झील के तट पर शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कार्यक्रम देखा गया। इस वर्ष योग दिवस का थीम 'स्वयं और समाज के लिए योग' था। इसने व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की एकजुट शक्ति, सीमाओं को पार करने और विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि से लोगों को एक साथ लाने का एक प्रमाण रहा है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी इन समारोहों में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, कर्तव्य पथ, और अब श्रीनगर में डल झील जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर योग सत्रों का नेतृत्व किया है।

योग का युवा मन और शरीर पर प्रभाव

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह ने युवा मन और शरीर पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया। शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के बावजूद, जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा योग के प्रति दिखाए गए उत्साह और प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। खास बात है कि प्रतिभागियों का योग के प्रति

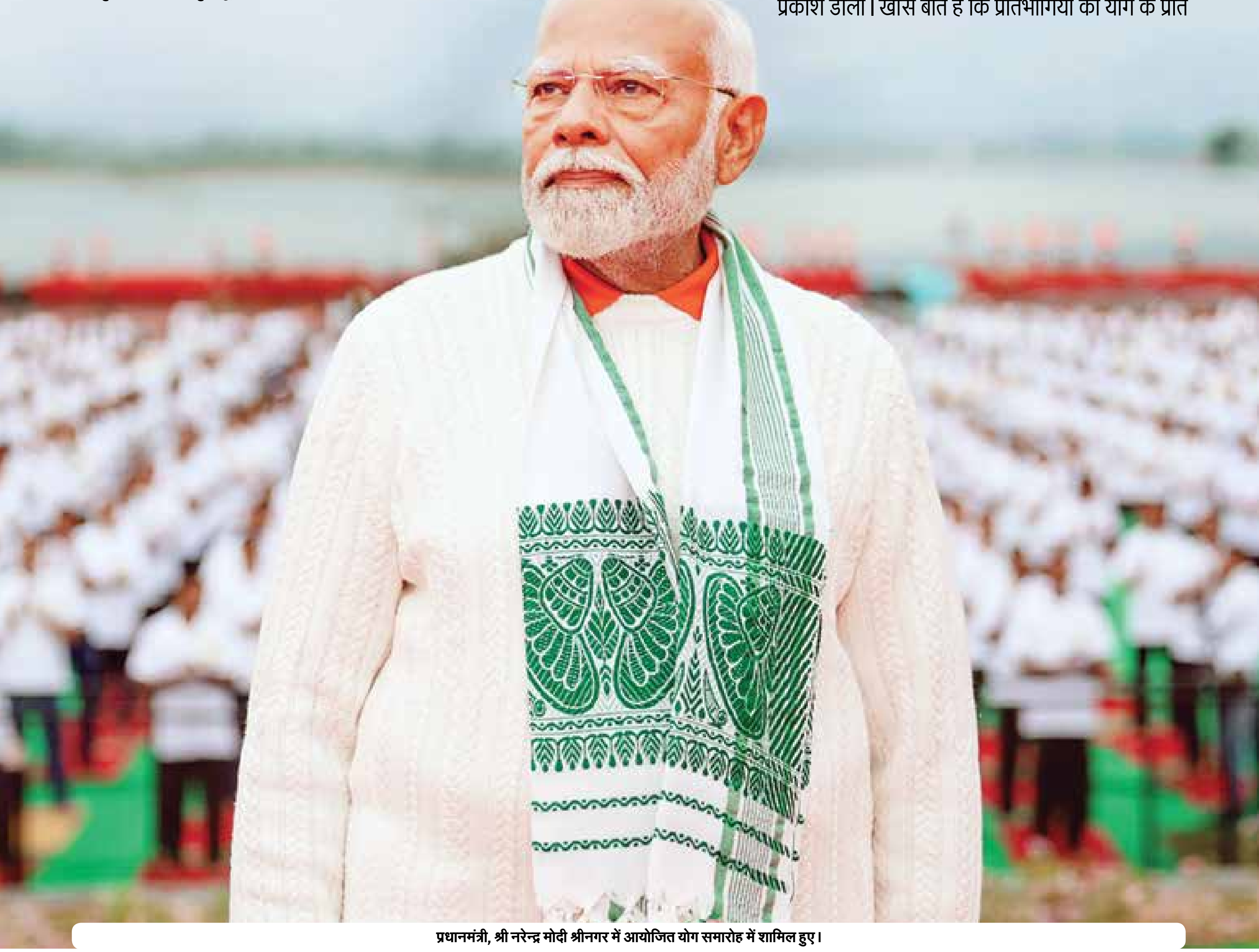

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी श्रीनगर में आयोजित योग समारोह में शामिल हुए।

योग स्वयं के लिए जितना महत्वपूर्ण, उपयोगी और सशक्त है, उतना ही समाज के लिए भी। जब योग से समाज को लाभ होता है, तो पूरी मानवता को लाभ होता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

समर्पण प्रतिकूल मौसम में भी दिखा।

जैसा कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया, योग दैनिक जीवन में एकीकृत होने पर सबसे प्रभावी हो जाता है। उन्होंने योग को रोजमर्रा की दिनचर्या का एक सरल, सहज हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ध्यान, योग का एक मुख्य पहलू है। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने का एक उपकरण है। योग के माध्यम से विकसित की गई मन की यह स्थिति न्यूनतम थकान के साथ अच्छे परिणाम देती है और विकर्षणों से बचने में मदद करती है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी

विश्व को भारत का सबसे बड़ा उपहार है योगः श्री अमित शाह

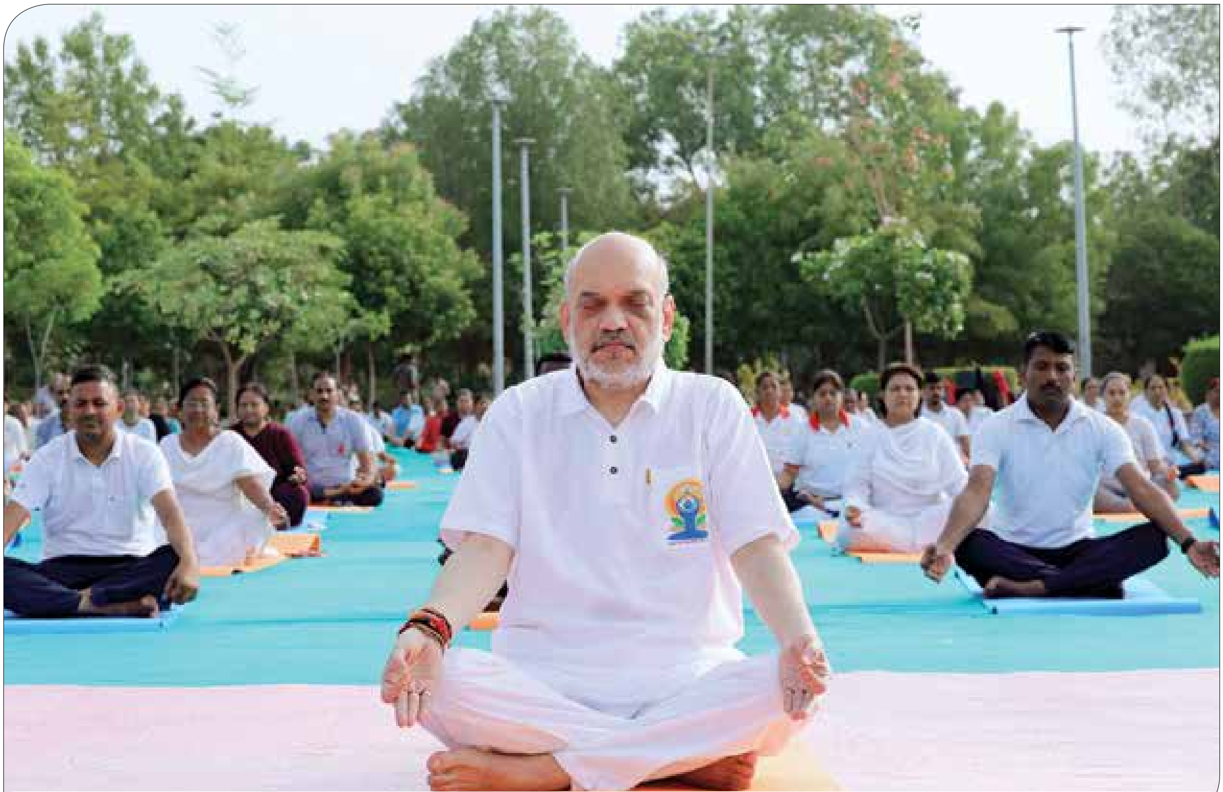

अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने भाग लिया।

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अहमदाबाद में योग चिकित्सकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने इस दिन के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस तथ्य को याद किया कि यह प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ही थे, जिन्होंने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव ने दुनिया को भारत के प्राचीन विज्ञान और योग के अनूठे उपहार से परिचित कराया। कुछ ही दिनों में 170 से अधिक देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने दुनिया और मानवता के लिए कई योगदान दिए हैं, जिनमें योग सबसे बड़ा उपहार है। उनका कहना है कि मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, 'योग हमारे दिमाग के भीतर की अपार शक्तियों को खोलने और वैश्विक कल्याण के लिए उन्हें आत्मा से जोड़ने का माध्यम है।'

कई आधुनिक बीमारियों के उपचार में योग के लाभों पर भी प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के लिए धन्यवाद, योग को मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच मिला है। आज, योग को दुनिया भर में अपनाया और सिखाया जाता है। विश्व स्तर पर लाखों लोगों ने योग को पूरे दिल से स्वीकार किया है और इसे बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

श्री अमित शाह ने गुजरात में योग के महत्व और उसकी उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा कि गुजरात सरकार और सभी के सहयोग से लगभग सवा करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज सुबह योगाभ्यास किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने योग को बढ़ावा देने और इसे खेल के रूप में भी मान्यता देने का काम किया है। श्री शाह ने यह भी कहा कि हमारे वेदों द्वारा दिए गए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सूत्र को चरितार्थ करने का काम योग कर रहा है। 21 जून को पूरी दुनिया में अलग-अलग समय पर योग का अभ्यास होता है, जिससे योग का वैश्विक महत्व और स्वीकार्यता सिद्ध होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वैश्विक कल्याण के मंत्र को लागू करने के लिए योग का निरंतर अभ्यास आवश्यक है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने कहा कि हमारे ऋषियों का दिया गया ज्ञान ही हमें आगे बढ़ा सकता है। हमारे शारीरिक सामर्थ्य, मन की शांति और कल्पनाओं के विस्तार, चेतना शक्ति के केंद्रीकरण और पूरे देश की सामूहिक ऊर्जा की जागृति के लिए योग से बड़ा कोई साधन हो नहीं सकता। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने योग दिवस की भेंट देकर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और ज्ञान का ध्वज फहराने का काम किया है।

श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

ने कहा, 'आध्यात्मिक यात्रा के अलावा, जो अंततः आएगी, ध्यान आत्म-सुधार और प्रशिक्षण का एक उपकरण है।'

एकीकरण शक्ति के रूप में योग

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे योग दुनिया भर में एक एकीकृत शक्ति बन गया है। उन्होंने कहा, '10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है, जिसका श्रेय व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों के सामूहिक प्रयासों को जाता है, जो एक साथ आए और योग का अभ्यास किया।'

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में रोजगार के प्रमुख स्रोत बनने के लिए योग और पर्यटन की क्षमता पर भी प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने योग को लोकप्रिय, प्रचलित बनाने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने वाले योग प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि पर गौर किया।

पिछले 10 वर्षों में योग के विस्तार के कारण इसके प्रति धारणाएं बदली हैं। प्रधानमंत्री ने एक नई 'योग अर्थव्यवस्था' के बारे में बात की। उन्होंने योग पर्यटन के प्रति बढ़ते आकर्षण और लोगों की प्रामाणिक योग सीखने के लिए भारत आने की इच्छा का उल्लेख किया। उन्होंने योग रिट्रीट, रिसॉर्ट्स, हवाई अड्डों और होटलों में योग के लिए समर्पित सुविधाओं, योग परिधान और उपकरण, व्यक्तिगत योग प्रशिक्षकों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये सभी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तैयार कर रहे हैं।

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का ध्यान जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार पर भी केंद्रित है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव एक वैश्विक कार्यक्रम था, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उत्साह और समर्पण के साथ योग सत्रों में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने डल झील से कार्यक्रम की झलकियां साझा कीं, जिसमें प्रतिभागियों और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य का प्रदर्शन किया गया। बारिश के बावजूद वहां जुटे अनगिनत लोगों का उत्साह बरकरार रहा।

योग की सार्वभौमिक अपील

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है, जबकि इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व का शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसने अपनी बातचीत के दौरान योग पर चर्चा न की हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग दुनिया के हर कोने में दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है।

दुनिया भर में योग की बढ़ती स्वीकार्यता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में तुर्कमेनिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान एक योग केंद्र के उद्घाटन को याद करते हुए कहा कि योग, आज देश में बेहद लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने आगे बताया कि तुर्कमेनिस्तान में चिकित्सा विश्वविद्यालयों ने योग चिकित्सा को शामिल किया है, सऊदी अरब ने इसे अपनी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया है और मंगोलियाई योग फाउंडेशन कई योग विद्यालय चला रहा है। प्रधानमंत्री ने यूरोप में योग की स्वीकार्यता की जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 1.5 करोड़ जर्मन नागरिक योग अभ्यासी बन चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि योग आज शोध का विषय बन गया है और कई शोध पत्र पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं।

नालंदा: भारत का वैश्विक ज्ञान केंद्र

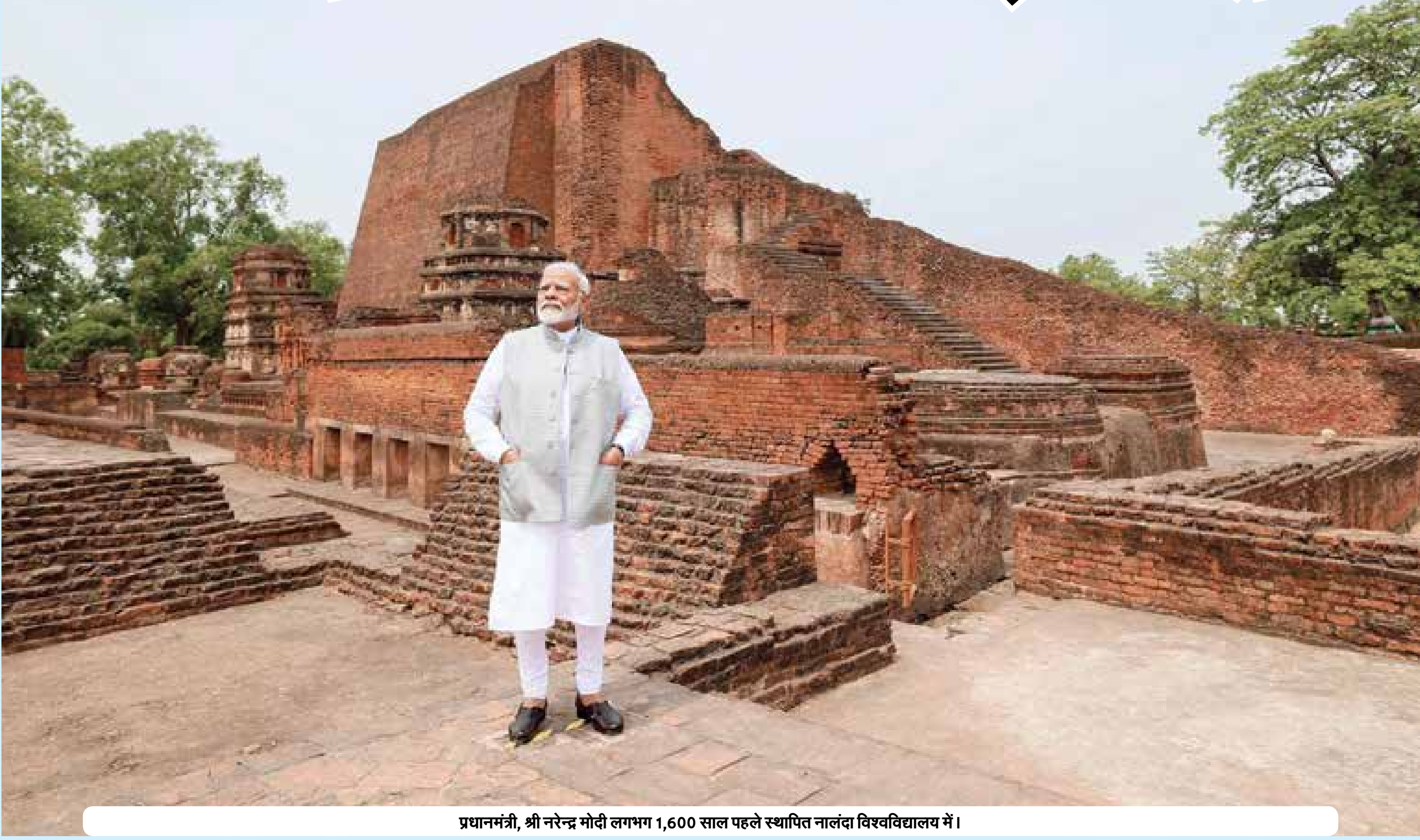

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी लगभग 1,600 साल पहले स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उनके विचारों को प्रकट करता है। प्रधानमंत्री ने 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर आशा व्यक्त की कि इस उद्घाटन समारोह से जुड़ा नालंदा का दौरा भारतीय विकास यात्रा के उत्कृष्टता का प्रतीक है। उन्होंने नालंदा को सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक पहचान और मंत्र माना है, जो ज्ञान के महत्व को प्रोत्साहित करता है। उनके शब्दों से स्पष्ट होता है कि नालंदा का उद्घाटन भारतीय शिक्षा के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत है, जो ज्ञान की प्रतिष्ठा को साकार करता है और भारतीय विरासत को बढ़ावा देता है।

भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक सहयोग से पुनर्निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय, भारत की प्राचीन शैक्षिक विरासत को पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने इस प्रयास के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला।

हमारा प्रयास दुनिया में सबसे व्यापक और संपूर्ण कौशल प्रणाली बनाना है। भारत में दुनिया की सबसे उन्नत अनुसंधान-उन्मुख उच्च शिक्षा प्रणाली होगी।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एक ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करना

लगभग 1,600 साल पहले स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। इस प्राचीन संस्थान के खंडहरों को वर्ष 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसके ऐतिहासिक खंडहरों के पास विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का उद्देश्य भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और दुनिया को याद दिलाना है कि मजबूत मानवीय मूल्यों वाले राष्ट्र अपने समृद्ध इतिहास को फिर से जीवंत करके बेहतर भविष्य बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नालंदा की विरासत भारतीय

बिहार के राजगीर में नवीनीकृत नालंदा विश्वविद्यालय परिसर।

सीमाओं से परे दुनिया, विशेषकर एशिया की विरासत को संजोए हुए है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा, कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है– 'न अलम ददाति इति 'नालंदा' अर्थात, जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो! प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडिमशन उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। वर्तमान में नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है।

भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित देशों के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि शैक्षिक विकास से अर्थव्यवस्था और संस्कृति मजबूत होती है। उन्होंने कहा, 'भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है जब हम स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। हम अपनी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव कर रहे हैं'।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरा मिशन भारत को दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत को फिर से दुनिया के सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए।'

केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी पहल का उल्लेख किया, जो युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता, कौशल और कल्पना को बढ़ावा देती है। डिजाइन मानसिकता, कम्प्यूटेशनल सोच, अनुकूली शिक्षा, अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान और गगनयान के प्रभाव और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के प्रसार जैसे कौशल विकसित करना। उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में दायर किए गए पेटेंट, प्रकाशित शोध पत्र और ₹1 लाख करोड़ के अनुसंधान कोष की स्थापना का उल्लेख किया।

वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत का बेहतर प्रदर्शन इन प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शिक्षा नीति को सुधारने और बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति की बात करते हुए भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं में नया आयाम जोड़ने का उल्लेख किया है। इस नीति के माध्यम से, भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा घरेलू स्तर पर मिल सके, जिससे उनके लिए लागत में बचत हो सके।

नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी उन्होंने वैश्विक परिसर की स्थापना के बारे में उम्मीद व्यक्त की है। इससे नालंदा विश्वविद्यालय को भी विश्व स्तरीय मानक पर उच्च स्तर पर पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर की नजरें भारत के युवाओं पर हैं, जो 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के दृष्टिकोण को साकार करने में मार्गदर्शन करेंगे।

नालंदा विश्वविद्यालय परिसर की यह अत्याधुनिक सुविधाएं भारतीय शिक्षा और ज्ञान के वैश्विक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान को सुनिश्चित करती हैं। इसमें 40 कक्षाएं, दो शैक्षणिक ब्लॉक, दो सभागार, छात्रावास, एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र, एक एम्फीथिएटर, संकाय क्लब, और एक व्यापक जल निकाय सहित सौर ऊर्जा, जल उपचार और रीसाइक्लिंग संयंत्र शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में बिहार के राज्यपाल, श्री राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, श्री पबित्रा मार्गेरिटा, बिहार के उपमुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सम्राट चौधरी उपस्थित थे। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर, प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया और कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

आपदा के समय उम्मीदों पर खरी उतरती है एनडीआरएफ

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एनडीआरएफ के दूसरे पर्वतारोहण अभियान 'विजय' की सफल वापसी का स्वागत किया।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें पारंपरिक राहत-केंद्रित मॉडल से हटकर शून्य-हताहत दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव को कम करना और अधिक से अधिक जीवन बचाना है। इसके तहत सक्रिय उपायों और तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि आपदाओं के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। शून्य-हताहत दृष्टिकोण और एनडीआरएफ के सफल अभियानों से यह स्पष्ट है कि भारत आपदा प्रबंधन में एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली की दिशा में अग्रसर है। इन प्रयासों से आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और अधिक जीवन बचाने में सहायता मिलेगी।

29 जून को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री, अमित शाह ने नई दिल्ली में 'ऑपरेशन विजय' के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के दूसरे पर्वतारोहण अभियान का स्वागत किया। यह अभियान हिमाचल प्रदेश में 21,625 फुट ऊंचे माउंट मनिरंग की सफल चढ़ाई पर आधारित था।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पर्वतारोहण अभियान की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभागियों की नहीं, बल्कि पूरे एनडीआरएफ की है। उन्होंने बल के समर्पण और ताकत के प्रतीक 'ऑपरेशन विजय' में सफल होने वाले 35 कर्मियों को बधाई दी।

श्री शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन काफी विकसित हुआ है। पहले, पूरा ध्यान राहत केंद्रित था, लेकिन वर्तमान में अधिक फोकस शून्य-हताहत दृष्टिकोण पर होता है। सरकार का लक्ष्य आपदाओं को रोकना और उनके प्रभाव को कम करना है। पिछले एक दशक में, भारत की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया है।

> **एनडीआरएफ के जवानों को देखकर आपदा में फंसे लोगों का हौसला कई गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार पर्वतारोहण अभियान में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे 35 जवानों ने पल-पल जागरूकता के साथ अपने आप को लक्ष्य के साथ जोड़ा है, उसी प्रकार हमारे बल को जीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य के साथ स्वयं को जोड़ना चाहिए।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के एकीकरण और आपदा प्रबंधन में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने से संबंधित अप्रोच के मामले में ये हमारी बहुत बड़ी यात्रा रही है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपदा से निपटने के लिए दुनियाभर की बेस्ट प्रैक्टिसिस को हमने भारत में जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग, बल का

केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने एनडीआरएफ के दूसरे पर्वतारोहण अभियान 'विजय' को दिल्ली में माउंट मनिरंग के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने भारत में आपदाओं से निपटने के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीदों पर खरी उतरी है। देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आती है तो सभी लोग एनडीआरएफ की तरफ देखते हैं। यह विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डायल 112 हो, मौसम, दामिनी, मेघदूत इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन हो या अर्ली वार्निंग का सिस्टम हो...सरकार हर तरह से एनडीआरएफ को वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करवा रही है।

हौसला बढ़ाने, बल का गठन करने, बल की पर्याप्त संख्या, इतने बड़े देश में हर जगह बल के जवानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपदा के आंकलन के लिए अग्रिम सूचना के माध्यम से एनडीआरएफ और एनडीएमए का एक विजयी गठजोड़ बनाने का काम सरकार के इन 10 साल में हुआ है।

एनडीआरएफ को आपदाओं के प्रति त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चाहे तुर्की, सीरिया, नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो या हाल ही में आए चक्रवात बिपोरजॉय से, एनडीआरएफ ने लगातार अपनी विशेषज्ञता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है।

श्री शाह ने आपदा प्रबंधन के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और एनडीआरएफ के लिए बजट आवंटन '66,000 करोड़ (2004-2014) से बढ़कर' 2 लाख करोड़ (2014-2024) हो गया है। यह वृद्धि वैज्ञानिक सहायता और आधुनिक संसाधनों के साथ आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्री शाह ने कहा कि डायल 112 हो, मौसम, दामिनी, मेघदूत इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशन हो या अर्ली वार्निंग का सिस्टम हो, केंद्र सरकार हर तरह से एनडीआरएफ को वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करवा रही है।

एनडीआरएफ की कार्यकुशलता और पेशेवर रवैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। कई बार एनडीआरएफ की टीमों ने विदेशों में भी राहत और बचाव कार्यों में हिस्सा लिया है। एनडीआरएफ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाती है। ड्रोन, रोबोटिक्स, और जीआईएस तकनीकों का इस्तेमाल करके यह आपदा स्थलों पर स्थिति का मूल्यांकन और बचाव कार्यों को अधिक सटीकता से अंजाम देती है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने यह पुष्टि की कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की चिंता और जागरुकता ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उनकी नेतृत्वकारी क्षमता और दूरदर्शिता ने आपदा प्रबंधन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने हाल ही में एनडीआरएफ कर्मियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते की मांग को स्वीकार करने की घोषणा की है। यह भत्ता 16,000 एनडीआरएफ कर्मियों को 40 प्रतिशत की दर से मिलेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया है, जिससे एनडीआरएफ कर्मियों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा सके।

इसके अलावा, श्री अमित शाह ने यह भी घोषणा की कि अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक टीम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में सभी आउटडोर और इंडोर खेलों में हिस्सा लेगी। इस पहल के लिए एक पूरा रोडमैप तैयार किया जा चुका है और जल्द ही इसका मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में खेलों को संस्कार के रूप में स्थापित करना है, जिससे बलों के जवानों में खेलों के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ सके।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनावों के सफल क्रियान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की, जिसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ।

ब्यूरो

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर एक मिसाल कायम की है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता है और सुरक्षा बल आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में सराहनीय बदलाव आए हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में शांतिपूर्ण मतदान और उच्च मतदान इस व्यापक परिवर्तन का एक बेमिसाल उदाहरण है।

16 जून को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा मुद्दों पर गहरी चर्चा की। इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहज समन्वय को मजबूत करने, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने का फैसला किया गया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने सीमा पार से

अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते जवान।

जम्मू- कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है।

आतंकवादियों द्वारा खोदे गए सुरंगों का पता लगाने के लिए स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने और आधुनिक तकनीक, ड्रोन अपनाने पर जोर दिया।

उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति की पुष्टि करते हुए, श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

श्री शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है और बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री अजीत डोभाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, श्री मनोज सिन्हा, थल सेनाध्यक्ष जनरल, श्री मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू-कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए उच्च सतर्कता बनाए रखने और सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सुरक्षित वातावरण के महत्व पर जोर देते हुए, श्री शाह ने सभी संबंधित एजेंसियों को व्यापक सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तीर्थयात्री बिना किसी डर या असुविधा के अपनी यात्रा कर सकें। यह निर्देश 16 जून को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिया गया। श्री शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट समन्वय और एक मजबूत मानक संचालन प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक और पर्यावरण-अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पिछले साल 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र दर्शन किए थे और इस साल की यात्रा (जो 29 जून को शुरु हुई है) में पंजीकरण, काफिले की आवाजाही, शिविर सुविधाओं, चिकित्सा सेवाओं और कई अन्य सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है।

₹36 करोड़ की लागत से बने 30 स्मार्ट स्कूलों का ई-लोकार्पण

अहमदाबाद के एक स्मार्ट स्कूल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, बच्चों के साथ ।

ब्यूरो

21 जून को गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने ₹36 करोड़ की लागत से बने 30 स्मार्ट स्कूलों का ई-लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बने इन स्मार्ट स्कूलों का विवरण और उनके लाभ पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इनमें घाटलोडिया विधानसभा में 9 स्मार्ट स्कूल, वेजलपुर विधान सभा क्षेत्र में 10, नारणपुरा में 4 और साबरमती में 7 स्मार्ट स्कूल का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 30 स्मार्ट स्कूलों के लोकार्पण से 10 हजार से अधिक बच्चों को नई शिक्षा नीति का सीधा फायदा मिलेगा और उनके जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलेगा। श्री शाह ने कहा कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के कुल 69 में से 59 स्कूल स्मार्ट स्कूल बन गए हैं और जो स्कूल बचे हैं वो भी जल्द ही स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित किए जाएंगे। इन स्मार्ट स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल एम्पावरमेंट को शामिल किया गया है। इसके साथ ही गणित, विज्ञान प्रयोगशालाएं, फ्यूचर क्लासरूम, थ्री-डी एजुकेशनल चार्ट, थ्री-डी पेंटिंग और भारतीय संस्कृति के सारे पहलुओं का अभ्यास भी सम्मिलित किया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2024 के लोक सभा चुनावों के बाद पहली बार वे गुजरात आए हैं और मंत्री तथा सांसद बनने के बाद यहां उनका पहला कार्यक्रम समाज के निम्न और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का उन पर सांसद के रूप में भरोसा करने के लिए वे हमेशा गांधीनगर की जनता के ऋणी रहेंगे और आने वाले पांच साल गांधीनगर के हर क्षेत्र की प्रगति और विकास के साथ सबसे विकसित संसदीय क्षेत्र बनाने के प्रति कटिबद्ध रहेंगे।

> **30 स्मार्ट स्कूलों के लोकार्पण से 10 हजार से अधिक बच्चों को नई शिक्षा नीति का सीधा फायदा मिलेगा और उनके जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलेगा।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री भूपेन्द्र पटेल सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे छात्रों को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और स्मार्ट स्कूलों के महत्व पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री परिषद

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग, जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री

1	श्री राजनाथ सिंह	रक्षा
2	श्री अमित शाह	गृह एवं सहकारिता
3	श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन, राजमार्ग
4	श्री जगत प्रकाश नड्डा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन और उर्वरक
5	श्री शिवराज सिंह चौहान	कृषि एवं किसान कल्याण; ग्रामीण विकास
6	श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त और कॉर्पोरेट कार्य
7	श्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश
8	श्री मनोहर लाल	आवासन एवं शहरी कार्य; ऊर्जा
9	श्री एच. डी. कुमारस्वामी	भारी उद्योग; इस्पात
10	श्री पीयूष गोयल	वाणिज्य और उद्योग
11	श्री धर्मेंद्र प्रधान	शिक्षा
12	श्री जीतन राम मांझी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
13	श्री राजीव रंजन सिंह	पंचायती राज; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
14	श्री सबार्नंद सोनोवाल	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
15	श्री वीरेंद्र कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
16	श्री किंजरापु राममोहन नायडू	नागर विमानन
17	श्री प्रल्हाद जोशी	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा
18	श्री जुएल ओराम	जनजातीय कार्य
19	श्री गिरिराज सिंह	वस्त्र
20	श्री अश्विनी वैष्णव	रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
21	श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया	संचार; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
22	श्री भूपेंद्र यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
23	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत	संस्कृति; पर्यटन
24	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	महिला एवं बाल विकास
25	श्री किरेन रिजिजू	संसदीय कार्य; अल्पसंख्यक कार्य
26	श्री हरदीप सिंह पुरी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
27	श्री मनसुख मांडविया	श्रम एवं रोजगार; युवा कार्यक्रम एवं खेल
28	श्री जी. किशन रेड्डी	कोयला; खान
29	श्री चिराग पासवान	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
30	श्री सी. आर. पाटिल	जल शक्ति

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्री राव इंद्रजीत सिंह	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना; संस्कृति
2	श्री जितेंद्र सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान , प्रधानमंत्री कार्यालय , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन , परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष विभाग
3	श्री अर्जुन राम मेघवाल	विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य
4	श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव	आयुष
5	श्री जयंत चौधरी	कौशल विकास और उद्यमिता

राज्य मंत्री

1	श्री जितिन प्रसाद	वाणिज्य एवं उद्योग; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
2	श्री श्रीपाद येसो नाईक	विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
3	श्री पंकज चौधरी	वित्त
4	श्री कृष्ण पाल	सहकारिता
5	श्री रामदास अठावले	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
6	श्री रामनाथ ठाकुर	कृषि एवं किसान कल्याण
7	श्री नित्यानन्द राय	गृह
8	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; रसायन एवं उर्वरक
9	श्री वी. सोमन्ना	जल शक्ति, रेल
10	श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी	ग्रामीण विकास; संचार
11	श्री एस.पी. सिंह बघेल	मत्स्य पालन, पशुपालन और; पंचायती राज
12	सुश्री शोभा करंदलाजे	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, श्रम एवं रोजगार
13	श्री कीर्तिवर्धन सिंह	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; और विदेश
14	श्री बी.एल. वर्मा	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
15	श्री शान्तनु ठाकुर	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
16	श्री सुरेश गोपी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; पर्यटन
17	श्री एल. मुरुगन	सूचना एवं प्रसारण; संसदीय कार्य
18	श्री अजय टम्टा	सड़क परिवहन और राजमार्ग
19	श्री बंडी संजय कुमार	गृह
20	श्री कमलेश पासवान	ग्रामीण विकास
21	श्री भागीरथ चौधरी	कृषि एवं किसान कल्याण
22	श्री सतीश चंद्र दुबे	कोयला; खान
23	श्री संजय सेठ	रक्षा
24	श्री रवनीत सिंह	खाद्य प्रसंस्करण; रेल
25	श्री दुर्गादास उइके	जनजातीय कार्य
26	श्रीमती खडसे रक्षा निखिल	युवा कार्यक्रम एवं खेल
27	श्री सुकांता मजूमदार	शिक्षा; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास
28	श्रीमती सावित्री ठाकुर	महिला एवं बाल विकास
29	श्री तोखन साहू	आवासन एवं शहरी कार्य
30	श्री राज भूषण चौधरी	जल शक्ति
31	श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा	भारी उद्योग; इस्पात मंत्रालय
32	श्री हर्ष मल्होत्रा	कॉर्पोरेट कार्य; सड़क परिवहन और राजमार्ग
33	श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक
34	श्री मुरलीधर मोहोल	सहकारिता; नागर विमानन
35	श्री जॉर्ज कुरियन	अल्पसंख्यक कार्य ; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
36	श्री पबित्रा मार्गेरिटा	विदेश; वस्त्र

असम राइफल्स ने 12 जून को मिजोरम के लांगतलाई जिले के हमावंगबुचुआ गांव में एंटी चाइल्ड लेबर डे पर जागरुकता व्याख्यान आयोजित किया। इस आयोजन का उद्देश्य कार्यबल में बच्चों के अवैध शोषण के बारे में जानकारी देना और बच्चों के लिए शिक्षा और सुरक्षा के अधिकार और श्रम से मुक्त बचपन को बढ़ावा देने के बारे में जागरुकता पैदा करना था।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपने 'मिड लेवल ट्रेनिंग कोर्स' के हिस्से के रूप में गाम्बिया के 35 सिविल सेवकों के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। 6 जून को आए इस प्रतिनिधिमंडल को भारतीय पुलिस और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ब्यूरो के महानिदेशक, श्री राजीव कुमार शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा हुई।

नागपुर में स्थापित नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (एनएफएससी) उत्कृष्टता की विरासत वाला एक प्रमुख संस्थान है, जो जीवन बचाने और संपत्ति की रक्षा करने के महान मिशन के साथ तकनीकी विशेषज्ञता को अद्वितीय रूप से जोड़ता है। फायर इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान करने वाले देश के एकमात्र संस्थान के रूप में एनएफएससी, महानिदेशक (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित होता है। एनएफएससी से फायर इंजीनियरिंग डिग्री धारक विविध करियर अपना सकते हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में शोधकर्ताओं, डिजाइनरों, सलाहकारों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अग्निशमन अधिकारियों, सुरक्षा अधिकारियों या एसएचई विशेषज्ञों की भूमिकाएं शामिल हैं। एनएफएससी के फायर इंजीनियरों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मांग है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। एनएफएससी ने मूल रूप से वर्ष 1957 में नागपुर जाने से पहले, उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपना परिचालन शुरू किया था। वर्ष 1978 से एनएफएससी अग्नि इंजीनियरिंग शिक्षा में अग्रणी रहा है, जो भारत में अग्नि, आपातकालीन और बचाव सेवाओं के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे रहा है।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में गृह मंत्रालय देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य करता रहेगा। साथ ही उनके नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि' की दृष्टि से किसानों और गांवों को सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगा।

श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037